राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दायित्व

अधिसूचित एजेन्डा के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13 एवं 14 जुलाई को होगी। हम उच्च प्राथमिकता के आधार पर सजर्मी पर संगठन को मजबूत करने की पहल सहित विगत चुनाव के संबंध में गहन विचार करेंगे। संगठित होकर सदस्यता वृद्धि करने सहित शाखा/जिला स्तर पर अपने कार्य मजबूत करने के तरीकों पर विचार करेंगे। कम्पनी की आर्थिक जीवंतता, कर्मचारियों का पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, नियम 5511 बी का विरोध, 78.2 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर मकान किराये भत्ते का भुगतान एनईपीपी में एस सी/एस टी कर्मियों के लिए छूट स्टैगनेशन, टावर कम्पनी तथा एमटीएनएल के साथ विलयन, बिजनेस एरिया के गठन का कर्मचारियों पर प्रतिकुल प्रभाव आदि हमारे प्राथमिकता आधारित मुद्दे हैं। बोनस के अधिकार की बहाली तथा प्रबंधन से वार्ता कर बोनस का भुगतान करना भी हमारे लक्ष्य में शामिल है। वेतन पुननिरीक्षण, सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायधीश श्री सतीश चंद्र जी की नेतृत्व में अध्किारी वर्ग के लाये तृतीय वेतन पुननिरीक्षण समिति का गठन कर दिया है। यह समिति छः माह में अपनी अनुशंसा सौंपेगी तथा इस पर सरकार द्वारा निर्णय के उपरान्त यह 1 जनवरी 2017 से लागू किया जायेगा। इससे हमारे कर्मचारियों की आशाएं जागृत हो गई हैं क्योंकि बीएसएनएल में शामिल बहुसंख्या कर्मियों के लिए यह अंतिम वेतन पुननिरीक्षण होगी अतएवं वेतन पुनर्निधारण के साथ पेंशन की पुननिरीक्षण एवं पुननिरीक्षण होना आवश्यक है। याद दिलाना आवश्यक है कि सचिव, दूरसंचार ने आश्वासन दिया था कि वेतन पुननिरीक्षण के समय विशेष संदर्भ के द्वारा इस मुद्दे का उठाया जायेगा। पिछले समय द्वितीय वेतन पुननिरीक्षण से पूर्व वेतन समझौता हेतु सातवें दौर की वार्ता बुलाई गई थी लेकिन इस बार तृतीय वेतन पुननिरीक्षण के पूर्व अगली वार्ता के लिए किसी भी लोक उपक्रम के श्रमिक संगठनों ने आवाज नहीं उठाई। लोक उपक्रम विभाग ;डी.पी.ई.द्ध से आठवें दौर की वेतन समझौता की मांगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी द्वितीय प्राथमिकता बीएसएनएल प्रबंधन पर दवाब बनाते हुए एक सापेक्ष द्वितीय वेतन समझौता समिति गठित करना। यह समिति नाम के लिए नहीं अपितु पूर्ण रूप से अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन को शामिल करते हुए सशक्त समिति गठित होनी चाहिए। हमारी तीसरी प्राथमिकता सभी नॉन एक्जीक्यूटिव यूनियन के साथियों को शामिल करते हुए व्यापक समिति गठित करने का प्रयास दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा करने का प्रयास दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा करनी होगी एवं हमारी चौथी प्राथमिकता होगी हर कदम पर सभी संगठनों की व्यापक सहमति के साथ आगे बढ़ना। एक्जीक्यूटिव कर्मियों की वेतन वृद्धि की मांग को प्रबंधन ने स्वीकृति दे दी है वहीं ग्रप डी/आर.एम ;सहायक तकनीकी सहायकद्ध के वेतन उत्थान की मांग ठुकरा दी है। हमें एक जुट, होकर उस समूह का ग्रूप सी की स्तर के वेतन मांग सुनिश्चित करनी होगी। सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 11 जुलाई 2016 से सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों में सुधार के लिए जंगे मैदान में उतर रहे हैं। जैसा कि लोक उपक्रम के लिए आहूत तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के संदर्भ में वर्णित है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव तृतीय पी.आर. सी.पर भी होगा। बहुसंख्यक केन्द्रीय श्रमिक संघों ने वर्तमान केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक लड़ाई का शंखनाद किया है। हमारा कर्तव्य है कि हम श्रमिक समुदाय की मुख्यधारा के साथ चलें। आइये दिल्ली में हम मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगें।

सी.एच.क्यू. से सभांर